ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

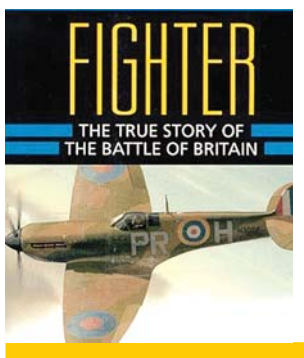

The new boy is in trouble

Well, now Winter knew true war stories. When old men decided to barter young men for pride and profit, the transaction was called war

Rare 200-year-old Pichwai

'Pichwai Through the Ages: Art and Worship,' a meticulously curated exhibition by ICA Gallery and Darshanam, opened its doors

विपक्ष यूपी चुनाव में आरक्षण बम फोड़ने की तैयारी में है, भाजपा को डैमेज करने के लिए

लोग भूले नहीं हैं, कुछ अर्सा पूर्व बिहार चुनाव में मोहन भागवत ने कहा था, आरएसएस आरक्षण हटाने का सोच रही है, तब भाजपा वहाँ हार गई थी और लालू यादव की सत्ता में वापसी हुई थी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 अगस्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब एक ऐसा मुद्दा आकार लेता दिखाई दे रहा है, जो आगे चलकर "बम" में बदल सकता है और भाजपा के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप है कि वह आरक्षण को खत्म करने का बैकडोर तरीका अपना रही है, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य प्रभावित वर्गों के बीच बेहद भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा है।

- यह मुद्दा इतना गंभीर है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के सारे समीकरण बिगाड़ सकता है। अखिलेश यादव और कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि भाजपा को मात दी जा सके।
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकार ने बैकडोर से आरक्षण खत्म करने की योजना रची है।
- खड़गे ने आरोप लगाया, आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है।

आरक्षण मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों में दिया जाता है और विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इससे एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है।

एक तरफ जोर-शोर से कहा जा रहा है कि नौकरियां नहीं हैं और बेरोज़गारी तेजी से बढ़ रही है।

दूसरी तरफ सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और उन्हें जानबूझकर नहीं भरा जा रहा है।

क्या यह आरक्षण को खत्म करने की कोई रणनीति है? यही वह अहम सवाल है जो अब उठाया जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने एक ट्वीट में इसी मुद्दे को उठाया। उन्होंने लिखा:

चोर दरवाज़े से मोदी सरकार ने आरक्षण ख़त्म करने की योजना रची !!

2015 में केन्द्र सरकार में 4.21 लाख पद खाली थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 8.24 लाख हो गई।

रेलवे में 2.40 लाख पद खाली हैं। डिफेंस में 2.41 लाख। गृह मंत्रालय में 1.10 लाख।

पीएसयू में 5.1 लाख स्थायी नौकरियां खत्म हो गईं। ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई।

सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है।

सरकारी पद खाली रखो तो आरक्षण का अवसर खत्म।

पीएसयू बेचो तो आरक्षित नौकरियां खत्म।

स्थायी नौकरी को ठेके में बदलो तो आरक्षण खत्म।

आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफ़ी है।

सामाजिक न्याय विरोधी भाजपा का यही एजेंडा है।

पद खाली रखो। पीएसयू बेचो। ठेकेदारी बढ़ाओ और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से उनका संवैधानिक हक छीन लो।

बाबा साहेब के संविधान से मिले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत खत्म

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारी वर्षा के कारण दिल्ली से 15 फ्लाइट्स डायवर्ट करनी पड़ी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 अगस्त। सोमवार को दिल्ली में भारी बारिश और गरज-चमक के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। इससे शहर के हवाई अड्डे पर आने और जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा और इससे जुड़े अन्य मार्गों पर भी उड़ानों में देरी हुई।

खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से कुल 15 उड़ानों का मार्ग

- इनमें से तीन अन्तर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स थीं।

बदल दिया गया। इनमें तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थीं।

इनमें से 12 उडानों को जयपुर, दो को चंडीगढ़ और एक को लखनऊ भेजा गया।

गौरतलब है कि दक्षिण दिल्ली और आसपास के इलाकों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट और मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया।

स्पाइसजेट सहित, कई एयरलाइनों ने यात्रियों को सलाह जारी कर चेतावनी दी कि खराब मौसम के कारण आगे की उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइनों ने यात्रियों से हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने को कहा।

एयर इंडिया ने भी सलाह जारी करते हुए कहा, "खराब मौसम के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर धमकियाँ मिली

इस बार जो धमकियाँ मिली हैं, उनमें कश्मीरी पंडितों के नाम, पते, फोन नम्बर तक दिए गए हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 अगस्त। यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (जिसे प्रतिबंधित संगठन "लश्कर-ए-तैयबा" का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है) की ओर से जारी एक नई ऑनलाइन हिट लिस्ट सामने आने के बाद, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों और निवासियों में फिर चिंता बढ़ गई है। इस बार धमकी में पहले के मुकाबले बहुत अधिक सटीक जानकारी दी गई है।

पहले मिली धमकियों से अलग, इस नए पत्र में निशाना बनाए गए लोगों के नाम, फोन नंबर और उनके घरों के पूरे पते जैसी निजी जानकारी दी गई है, जिससे डेटा लीक होने की आशंका पैदा हो गई है। इसमें कश्मीर और जम्मू दोनों जगहों के लोगों की जानकारी है।

सुरक्षा एजेंसियां पत्र की वास्तविकता की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसे फैलाने के पीछे कौन लोग हैं।

यह डराने-धमकाने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी ही धमकी मिलने के बाद, प्रशासन ने प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज (पीएमआरपी) के तहत भर्ती किए गए अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी थी और पूरी घाटी में ट्रांजिट कैंपों की सुरक्षा बढ़ा दी थी।

- यूनाइटेड लिबरेशन काउन्सिल, जो कि प्रतिबंधित संगठन "लश्कर-ए-तैयबा" का प्रॉक्सी है, ने सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन हिट लिस्ट जारी की है। लिस्ट में कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों के कश्मीरी पंडितों के नाम हैं।
- सुरक्षा एजेंसियाँ लिस्ट की प्रामाणिकता का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं और लिस्ट जारी करने वालों का पता लगाया जा रहा है।
- इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत सरकारी नौकरियां मिली थीं। लोगों के नाम, पते, फोन नम्बर के साथ गाड़ियों के नम्बर तक दिए गए हैं।

हालांकि, इस बार धमकी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। आतंकवादी संगठन ने पीएमआरपी कर्मचारियों के नाम और संपर्क संबंधी जानकारी (कॉन्टैक्ट डीटेल) के साथ-साथ, कश्मीर और जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों के पते (गली का नाम और घर के नंबर सहित) भी जारी किए हैं। कई मामलों में तो गाड़ियों के पंजीकरण नंबर भी दिए गए हैं।

कश्मीरी पंडितों को वापस बसने और अपनी पैतृक संपत्तियों को फिर से हासिल करने की कोशिशों को हतोत्साहित करने की कोशिश में, पत्र में समुदाय के सदस्यों को "गद्दार" और "सफेदपोश आतंकवादी" बताया गया है।

"रूट्स इन कश्मीर" के अमित रैना ने इस मुद्दे पर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और कश्मीर केन्द्रित राजनीतिक नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

रैना ने कहा, "90 के दशक में भी वे मूक दर्शक बने रहे थे, जिसके कारण पांच लाख कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से पलायन करना पड़ा। इस बार भी वे चुप हैं।"

धमकी भरे पत्र में यह आरोप भी लगाया गया है कि निशाना बनाए गए लोग "आरएसएस के एजेंडे" को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर में हैं।

अजीत डोभाल दो दिन के चीन दौरे पर, सीमा विवाद पर बात करेंगे

सीमा और अरूणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों में विवाद इतना गहरा गया है कि उससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 अगस्त। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 24 अगस्त को दो दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे, जहां वे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा विवाद पर "विशेष प्रतिनिधियों" की वार्ता में हिस्सा लेंगे। यह वार्ता ऐसे समय हो रही है, जब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुप्रत्याशित भारत यात्रा को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

यह बैठक ऐसे समय भी हो रही है, जब सीमा और अरुणाचल प्रदेश को लेकर मतभेद नई दिल्ली और बीजिंग के संबंधों पर लगातार असर डाल रहे

- चीन के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सीमा विवाद के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों पर और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी बात होगी।
- 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने पर अनिश्चितता बनी हुई है।

हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद, दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। हालांकि, इसके बाद दोनों पक्षों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

वार्ता की घोषणा करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि डोभाल और वांग यी सीमा विवाद के साथ-साथ, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत-चीन "विशेष प्रतिनिधि वार्ता" सीमा विवाद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी- बीएल संतोष

पटियाला, 24 अगस्त। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने सोमवार को कहा कि पार्टी आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर अपने दम पर

- भाजपा राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) ने पंजाब के दौरे के दौरान पटियाला में ज़ोनल बैठक में यह बात कही।

चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी।

पटियाला में अपने दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे के पहले दिन पहली जोनल बैठक को संबोधित करते हुए संतोष ने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा इस बदलाव को वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इससे पहले, पंजाब भाजपा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरक्षण व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने की माँग जोर पकड़ रही है

सोशल मीडिया पर शुरु हुआ आरक्षण आंदोलन जंतर-मंतर और रामलीला मैदान पर विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 अगस्त। जो अभियान सोशल मीडिया पर एक पेज से शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उसके इंस्टाग्राम पेज के 56 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए, वह अब सड़कों तक पहुंच चुका है। हजारों लोग नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में जुटे। सवाल उठ रहे हैं कि अचानक शुरू हुआ यह छोटा-सा विरोध प्रदर्शन आखिर आंदोलन में कैसे बदल गया और इसे इतनी तेजी से समर्थन क्यों मिलने लगा? आगे क्या हो सकता है और इसका राजनीतिक तथा संवैधानिक रूप से क्या असर पड़ सकता है?

'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों और अन्य प्रतिभागियों

- सवाल यह है कि आरक्षण के खिलाफ बढ़ते विरोध का राजनीतिक और संवैधानिक रूप से क्या असर पड़ेगा?
- सुप्रीम कोर्ट, आरक्षण पर कई महत्वपूर्ण फैसले पहले ही दे चुका है। अदालत ने क्रीमीलेयर के निर्धारण में माता-पिता की नौकरी के पद व सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखने के लिए कहा है।

की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

जाति के बजाय, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। आंदोलनकारियों का तर्क है कि तथाकथित ऊंची जातियों में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने निम्न जाति के समकक्षों की तरह आर्थिक रूप से गरीब हैं।

ओबीसी वर्ग में उन लोगों को आरक्षण का लाभ न दिया जाए, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये या उससे अधिक है।

एक परिवार में केवल एक सदस्य को आरक्षण का लाभ दिया जाए, ताकि अन्य लोगों को भी समान अवसर मिल सके।

यूजीसी के दिशा-निर्देशों और एससी, एसटी, ओबीसी (अत्याचार निवारण) अधिनियम को वापस लेने की मांग भी की गई है।

'आरक्षण हटाओ आंदोलन' से जुड़े लोग पूरी आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं।

आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई महत्वपूर्ण फैसले दे चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने के अधिकार को बरकरार रखा है, ताकि आरक्षण का लाभ अधिक लक्षित (टारगेटेड) तरीके से जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाया जा सके।

अदालत ने यह भी कहा है कि ओबीसी उम्मीदवार के क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय केवल आय सीमा को ही नहीं, बल्कि माता-पिता की नौकरी के पद और सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मुझे अनुमति नहीं, पर गुजरात मुख्यमंत्री को इजाज़त'

हैदराबाद, 24 अगस्त। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने पर अब निशाना साधा है। सोमवार को रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल

- तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भूपेन्द्र पटेल को इन्वेस्टमेंट रोड शो के लिये अमेरिका जाने की इजाज़त कैसे दी गई।

को अमेरिका में इन्वेस्टमेंट रोडशो करने की इजाज़त क्यों दी गई, जबकि उनके अपने दौरे को पॉलिटिकल मंज़ूरी नहीं दी गई। सीएम रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुंबई के ऑटो और टैक्सी चालकों ने तीन दिन की हड़ताल आहूत की

ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने कांदिवली में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दीं और मराठी भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 अगस्त। मुंबई के कांदिवली इलाके में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दीं और मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि शहर में वाहन चलाने के लिए मराठी सीखने का दबाव "अनुचित" है। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग को लेकर तीन दिन की हड़ताल शुरू की, जिसके बाद कांदिवली लिंक रोड पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ।

महाराष्ट्र परिवहन विभाग एक नियम लागू कर रहा है, जिसके तहत ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को राज्य की प्रमुख भाषा मराठी का कामचलाऊ ज्ञान दिखाना जरूरी है।

महाराष्ट्र में करीब 9.65 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालक हैं। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के अनुसार, 1.65 लाख चालक मराठी का प्रशिक्षण ले चुके हैं और उन्हें प्रमाणपत्र भी मिल चुका है।

- ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने नियम बनाया है कि ऑटो और टैक्सी चालकों को काम चलाऊ मराठी भाषा आना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर 15 से 20 हज़ार रूपए का जुर्माना लगाने और लाइसैंस व परमिट रद्द करने का प्रावधान भी है।
- आंदोलन कर रहे ऑटो व टैक्सी चालकों ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में भाषा सीखने के लिए धमकाने की क्या जरूरत है, उन्होंने इसे अन्याय बताया।
- एक टैक्सी चालक ने कहा, मैंने मराठी सीखने की कोशिश की, पर सीख नहीं पाया, अब आखिरी रास्ता अपने शहर लौट जाना ही है। हमें लाइसैंस जारी करते समय मराठी की अनिवार्यता के बारे में बताना चाहिए था।
- महाराष्ट्र में करीब 9.65 लाख ऑटो व टैक्सी ड्राइवर हैं। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि 1.65 लाख चालक मराठी भाषा का प्रशिक्षण ले चुके हैं और उन्हें प्रमाण पत्र भी मिल चुका है।

राज्य भर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) चालकों की जांच कर रहे हैं और ऐसे चालकों को नोटिस जारी कर रहे हैं, जिन्हें मराठी भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। चालकों को भाषा सीखने के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर उनके बैज तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। मराठी सीखने से लगातार इनकार करने पर बैज और परमिट दोनों को स्थायी रूप से रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

प्रदर्शनकारियों में से एक चालक ने कहा, "हम मराठी सीखने की कोशिश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीजेपी 5 सितम्बर को दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च निकालेगी

नई दिल्ली, 24 अगस्त। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोमवार को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक 5 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च निकालने की घोषणा की। छात्र आंदोलन

- इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च का नेतृत्व नीट में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार वाले करेंगे।

के दौरान "संसद चलो" मार्च के बाद उनका यह दूसरा शांतिपूर्ण मार्च होगा।

सीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार, इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन सरकार की ओर से 25 जुलाई को किए गए वादों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)